सैंतीसवाँ प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(13.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/अग्रहायण, 1944(शक)

सीपीबी. सं. 1 खंड XXXVII

©2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित।

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक की ऋण योजनाओं, विशेष रूप से गुवाहाटी में, के बारे में ग्राहकों की धारणा और प्रभावशीलता तथा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री फणी धर दास से प्राप्त अभ्यावेदन। 1

परिशिष्ट

याचिका समिति की 12.12.2022 को हुई 25वीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 51

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ
6. डॉ. जयंत कुमार राय
7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. श्री बृजेन्द्र सिंह
9. श्री सुनील कुमार सिंह
10. श्री सुशील कुमार सिंह
11. श्री मनोज कुमार तिवारी
12. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
13. श्री राजन बाबूराव विचारे
14. रिक्त
15. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री आनंद कुमार हाँसदा - सहायक कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का सैंतीसवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक की ऋण योजनाओं, विशेष रूप से गुवाहाटी में, के बारे में ग्राहकों की धारणा और प्रभावशीलता तथा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री फणी धर दास से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति का यह सैंतीसवाँ प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 12 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में 37वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;

12 दिसंबर, 2022

21 अग्रहायण, 1944(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति

प्रतिवेदन

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक की ऋण योजनाओं, विशेष रूप से गुवाहाटी में, के बारे में ग्राहकों की धारणा और प्रभावशीलता तथा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री फणी धर दास से प्राप्त अभ्यावेदन।

श्री फणी धर दास ने दिनांक 25.02.2022 को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक की ऋण योजनाओं, विशेष रूप से गुवाहाटी में, के बारे में ग्राहकों की धारणा और प्रभावशीलता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में याचिका समिति के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

2. अभ्यावेदनकर्ता श्री दास ने अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि गुवाहाटी असम के औद्योगिक केन्द्रों में से एक है, जिसमें बहुत सी लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं जो इसके निवासियों को रोजगार प्रदान करती हैं और इस प्रकार, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4 से 5 वर्षों से, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनके आधार पर देश के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी ऋण योजनाएं असम राज्य सहित देश में पहले ही प्रचालित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी, जिसमें 16 एक्शन पॉइंट शामिल थे जो पहल के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि असम राज्य में 21 स्टार्टअप्स को पहले ही मान्यता दी जा चुकी है; तथापि, यह बहुत निराशा की बात है कि पूर्ववर्ती असम सरकार ने राज्य में स्टार्टअप नीतियां तैयार नहीं की थी जिसके कारण इन 21 स्टार्टअप्स को कोई अपेक्षित सहायता प्रदान नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप इन स्टार्टअप्स में केवल अल्प धनराशि का निवेश हुआ है। इस अगली कड़ी में, उन्होंने आगे कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक, जिन्हें गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अग्रणी बैंक माना जाता है, सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में पिछड़ गए हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान सहित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) हो,

जो इन ऋण योजनाओं के ग्राहकों की धारणा और प्रभावशीलता पर किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट है। इसलिए, अभ्यावेदनकर्ता ने याचिका सम्बन्धी समिति से गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त वाणिज्यिक बैंकों के साथ इन मुद्दों को उठाने का अनुरोध किया है।

3. याचिका सम्बन्धी समिति ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 95 के तहत जांच के लिए श्री फणी धर दास के अभ्यावेदन पर विचार किया, तदनुसार, अभ्यावेदन को वित्त मंत्रालय, (वित्तीय सेवाएं विभाग) को उसमें उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया।

4. इसके प्रत्युत्तर में, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने श्री फणी धर दास के अभ्यावेदन पर निम्नानुसार पृष्ठभूमि नोट प्रस्तुत किया है:-

<u>स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया</u>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास, नवाचार के सबसे मजबूत चालकों में से हैं और तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं तथा विकास में प्रणाली का सहयोग करने हेतु बड़े उद्यमों के लिए सहायक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष रूप से असम राज्य में एमएसएमई के विकास और वृद्धि हेतु ऋण सुविधाएं प्रदान करने के मामले में अग्रणी है। बैंक पीएमईजीपी, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के वित्तपोषण पर पहले से ही ध्यान केंद्रित करता आ रहा है।

ऐसी योजनाओं का सही तरह से कार्यान्वयन करने और बेरोजगार युवाओं को लाभ देने के लिए पूर्वोत्तर और विशेष रूप से असम राज्य में अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने हेतु एसबीआई लगातार सरकारी तंत्र के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं और इस मामले में सबसे आगे रहा है।

अब तक, एसबीआई ने असम राज्य में 46,350 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया और पीएमईजीपी जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से 838 करोड़ रुपये की राशि के ऋण सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बैंक की विभिन्न नियमित योजनाओं के साथ-साथ सरकारी रोजगार सृजन योजना के माध्यम से ऋण सुविधाओं की अनुमति देने के अलावा, एसबीआई ने एमएसएमई और कृषि के तहत अधिक रोजगार और आय पैदा करने के उद्देश्य से असम सहित सात राज्यों में "पूर्वोत्तर आर्थिक पुनरुद्धार योजना" नामक एक योजना भी तैयार की है।

एमएमएमई और कृषि के अंतर्गत असम राज्य में पूर्वोत्तर आर्थिक पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत एसबीआई ने कृषि खंड के अंतर्गत 24,333 इकाइयों को 280.23 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि संस्वीकृत की है, जिसमें 93,083 के रोजगार सृजन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 71.36 करोड़ रुपए की आय उत्पन्न हुई।

इसी तरह एमएसएमई के अंतर्गत भी 3,772 इकाइयों को 819.41 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे, जिससे वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 8,988 युवाओं को 81.94 करोड़ रुपए की आय हुई।

भारतीय स्टेट बैंक ने हमेशा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है तथा बैंकों की विभिन्न नियमित ऋण योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं स्टैंड-अप इंडिया आदि जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक आरएसईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का व्यापक गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल है और प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात, युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम आरंभ करने हेतु बैंक द्वारा क्रेडिट लिंकेज सहायतता प्रदान की जाती है।

जिलों में प्रमुख बैंक व अन्य बैंकों के सहयोग से किसानों, लघु उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों के बीच वित्तीय साक्षरता समारोह आयोजित करते हैं, ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं और अन्य बैंकिंग सेवाओं के बारे में संवेदनशील और जागरूक किया जा सके और जागरुकता निर्माण हो सके।

पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणी के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने असम राज्य में स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत 177 लाभार्थियों को कुल 38.23 करोड़ रुपए की राशि के ऋण संस्वीकृत किए है।

एसबीआई पूरे देश में एमएमएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें पूर्वोत्तर राज्य कोई अपवाद नहीं है। हम एमएसएमई क्षेत्र और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अपने कार्य-निष्पादन को बढ़ाने का आश्वासन देते हैं, जिसकी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की चर्चाओं के दौरान नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

एसबीआई हमेशा से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और हम इस प्रतिबद्धता पर कायम हैं।

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>

हमारे बैंक के पास विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए उत्पादों/योजनाओ की प्रचुरता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ कमजोर वर्ग सहित समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना तैयार की गई है।

बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार तनावग्रस्त एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों/हानि से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाएं हैं जैसे एमएसएमई को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता करने हेतु विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करना, जिनका उल्लेख निम्नानुसार है:-

(i) सरकार के नेतृत्व वाली पहल जैसे जीईसीएल, पीएमस्वनिधि, पीएमएमवाई, स्टैंडअपइंडिया, पीएमईजीपी आदि।

(ii) डिजिटल पहल जैसे कार्यशील पूँजी ऋण का ई-नवीनीकरण, ऋण प्रबंधन प्रणाली पीएनबी लैंस आदि।

(iii) फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई योजनाओ के प्रचार/एसएमएस के माध्यम से ग्राहक पहुँच में वृद्धि।

(iv) ग्राहकों के लिए तैयार रेकनर के रूप में कॉर्पोरेट वेबसाइट पर योजनाओं को अद्यतन करना।

असम राज्य में सरकार के नेतृत्व वाली पहल के तहत बैंक के पास अनुकूल ऋण जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ में)

योजना	*स्वीकृत खातों की संख्या*	*स्वीकृत राशि*
जीईसीएल (आरंभ से)	*7913*	*398*
पीएमस्वनिधि (आरंभ से)	*8385*	*9*
पीएमएमवाई (वित्त वर्ष 2021-22 में)	*24052*	*584*
पीएमईजीपी (वित्त वर्ष 2021-22 में)	*614*	*42*
स्टैंड अप इंडिया (वित्त वर्ष 2021-22 में)	*32*	*12*

<u>कमजोर वर्ग को ऋण:</u>

(राशि करोड़ में)

राज्य	*संवितरण के दौरान वितीय वर्ष 2021-22*		*31.03.2022 को बकाया*	
	खातों की संख्या	*राशि*	*खातों की संख्या*	*राशि*
अरुणाचल प्रदेश	*104*	*8*	*3408*	*67*
असम	*12540*	*141*	*200696*	*1395*
मणिपुर	*1758*	*77*	*19977*	*276*

मेघालय	536	21	3782	112
मिजोरम	246	17	6191	104
नागालैंड	197	6	2055	36
सिक्किम	221	15	862	50
त्रिपुरा	5370	81	48007	356
पूर्वोत्तर (राज्यों का योग)	20972	365	284978	2397
सम्पूर्ण पैन इंडिया के रूप में पीएनबी	1441369	41879	4755612	81889

31.03.2022 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं पर बकाया ऋण:

(राशि करोड़ में)

राज्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		कुल एससी/एसटी		महिला लाभार्थी	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
अरुणाचल प्रदेश	52	1	2647	83	2699	85	2147	53
असम	16174	211	24539	316	40713	527	74607	1192
मणिपुर	966	20	13995	232	14691	252	13974	263
मेघालय	91	3	3982	111	4073	114	3103	91
मिजोरम	13	1	4158	98	4171	99	3557	55
नागालैंड	25	1	3058	56	3083	57	1369	16
सिक्किम	156	14	570	41	726	55	809	57
त्रिपुरा	8893	101	26972	183	35865	284	19232	205
पूर्वोत्तर (राज्यों का योग)	26370	352	79921	1119	106291	1471	118798	1933
सम्पूर्ण पैन	488777	9180	235546	3861	724323	13041	1828597	77933

इंडिया के रूप में पीएनबी								

यूको बैंक

सरकार एमएसएमई को सहायता प्रदान करने पर बहुत जोर दे रही है और उभरते हुए एमएसएमई को आसान ऋण देने के लिए विभिन्न क्रेडिट योजनाएं चलाती है। वित्त वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक द्वारा फ्लैगशिप सरकारी योजनाओं में असम राज्य में दिए गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	*सरकार की ऋण योजना*	*दिया गया ऋण*	
		खातों की संख्या	*राशि*
1.	*पीएमएमवाई*	*9,719*	*29,667*
2.	*पीएमईजीपी*	*119*	*145*
3.	*स्टैंड अप इंडिया*	*13*	*377*
4.	*जीईसीएल*	*9,928*	*10,628*

उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित जोनल प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और स्टैंड अप इंडिया (एसयूआई) पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न क्रेडिट योजनाओं के बारे में शाखाओं को संवेदनशील बनाएं और इन योजनाओं के तहत मंजूरी/वितरण में तेजी लाएं।

5. श्री फणी धर दास के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों/उठाए गए बिंदुओं का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए समिति ने 2 जून, 2022 को गुवाहाटी का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा भी किया। उक्त अध्ययन यात्रा के दौरान समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

6. समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के ग्लोबल ऑपरेशन्स के आंकड़ों के आधार पर 31.03.2022 तक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक के कुल सकल अग्रिमों के बारे में जानना चाहा। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया कि:-

<u>स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया</u>

दिनांक 31.03.2022 तक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का कुल सकल अग्रिम 28,18,671 करोड़ रुपये था।

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>

दिनांक 31.03.2022 तक पंजाब नेशनल बैंक का कुल सकल अग्रिम 7,85,104 करोड़ रुपये था, जबकि असम राज्य के लिए यह 9,652 करोड़ रुपये था।

<u>यूको बैंक</u>

दिनांक 31.03.2022 तक यूको बैंक का सकल अग्रिम 1,29,777.34 करोड़ रुपये था, जबकि असम राज्य के लिए यह 9,652 करोड़ रुपये था।

7. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में वृद्धि आक्रामक ऋण प्रथाओं, जानबूझकर चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के कारण है, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/ एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:–

<u>स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया</u>

भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है, विशेषरूप से वर्ष 2008 के बाद विदयुत क्षेत्र में देश में बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि उच्च वृद्धि दर जारी रहेगी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इस प्रकार की वृद्धि की अपेक्षाएं प्रतिष्ठित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुरूप थीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी के दौरान, बैंकों ने वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को सहायता देने के लिए कॉरपोरेटो के साथ-साथ रिटेल

उधारकर्ताओं को बड़े पैमाने पर ऋण दिया। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है, विशेषरूप से वर्ष 2008 के बाद विदयुत क्षेत्र में देश में बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि उच्च वृद्धि दर जारी रहेगी। देश में अवसंरचना क्षेत्र में इस प्रकार की वृद्धि की अपेक्षाएं प्रतिष्ठित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुरूप थीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी के दौरान, बैंकों ने वितपोषण संबंधी आवश्यकताओं को सहायता देने के लिए कॉर्पोरेटो के साथ-साथ रिटेल उधारकर्ताओं को बड़े पैमाने पर ऋण दिया। हालांकि, वैश्विक वितीय संकट के बीच विभिन्न परियोजनाओं के लिए मांग अनुमानों में गिरावट आई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, खनन परियोजनाओं में प्रतिबंध और विद्युत, लोहा और इस्पात क्षेत्र को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी अनुमोदनों में देरी, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, मांग और आपूर्ति में अंतर और उपलब्धता में कमी के कारण अधिकांश कॉरपोरेट्स के लाभ में कमी आई। हालांकि, वैश्विक वितीय संकट के बीच विभिन्न परियोजनाओं के लिए मांग अनुमानों में गिरावट आई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, खनन परियोजनाओं में प्रतिबंध और विद्युत, लोहा और इस्पात क्षेत्र को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी अनुमोदनों में देरी, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, मांग और आपूर्ति में अंतर और उपलब्धता में कमी के कारण अधिकांश कॉरपोरेट्स के लाभ में कमी आई। इससे उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित हुई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए बढ़ने के पीछे यह सबसे अहम कारण है। अधिकांश बड़े एनपीए खाते पांच क्षेत्रों अर्थात् इस्पात, बिजली, दूरसंचार, अवसंरचना और वस्त्र क्षेत्र से थे। कॉरपोरेट क्षेत्र में दबाव ने खुदरा उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को भी प्रभावित किया, जिससे पूरे देश में खुदरा एनपीए के स्तर में वृद्धि हुई।

कॉरपोरेट और रिटेल उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण महामारी की अवधि के दौरान देखी गई कुछ गिरावट को छोड़कर बैंक की एनपीए स्थिति में सुधार हो रहा है। तथापि, हम समाधान के विभिन्न उपलब्ध तरीकों के माध्यम से लगातार प्रयासों के द्वारा तनावग्रस्त परिसंपतियों की वसूली में गति बनाए रखने में

सक्षम रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप में कमी के साथ, बैंक के कुल सकल एनपीए स्तरों में हाल के वर्षों में काफी सुधार हुआ।

<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र:</u>

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनपीए स्तरों में निरपेक्ष रूप से केवल मामूली वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण में बढ़ोतरी के बावजूद रिटेल पोर्टफोलियो में अग्रिमों के समग्र एनपीए प्रतिशत में कमी आई है। आस्तियों पर तनाव में वृद्धि मुख्य रूप से कोविड 19 रूपी व्यवधान के कारण आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती और उसके परिणामस्वरूप आय में गिरावट के कारण हुई है।

बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए जीईसीएल सुविधा का विस्तार किया है और विस्तारित मोराटोरियम और लंबी चुकौती अवधि के साथ सभी पात्र खातों में रिस्ट्रक्चरिंग(ऋण पुनर्गठन) सुविधा दी गई है।

सुस्थापित मजबूत/सक्रिय निगरानी तंत्र के साथ साथ कठोर मंजूरी प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार के कारण यह उम्मीद की जाती है कि आगामी महीनों में तनाव के स्तर में और कमी आएगी।

<u>खुदरा ऋण संबंधी आंकड़े</u>

(रुपये करोड़ में)

मंडल/ राज्य	अग्रिम	एनपीए	एनपीए %	अग्रिम	एनपीए	एनपीए %
	31.03.2021			31.03.2021		
उत्तर-पूर्व	49,728	1,730	3.51%	58,606	1,759	3.00%
असम	-	1,119	-	-	1,159	-

पंजाब नेशनल बैंक

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धोखाधड़ी के मामले (ऋण धोखाधड़ी) आरबीआई के विवरण में निम्नानुसार बताए गए है:-

(राशि करोड़ में)

धोखाधड़ी के प्रकार	*वित्त वर्ष 2019-2020*		*वित्त वर्ष 2020-2021*		*वित्त वर्ष 2021-2022*	
	संख्या	*राशि*	*संख्या*	*राशि*	*संख्या*	*राशि*
उधार धोखाधड़ी (ऋण धोखाधड़ी)	*402*	*23462*	*140*	*10010*	*142*	*9554*

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये गए उधार धोखाधड़ी मामलों (ऋण धोखाधड़ी) की राशि के संबंध में गिरावट की प्रवृति है। इसके अलावा, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से असम के संबंध में आरबीआई को रिपोर्ट किए गए उधार धोखाधड़ी के मामले (ऋण धोखाधड़ी) निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ में)

*उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंध में भा.रि.बैं. को रिपोर्ट किए गए उधार धोखाधड़ी के मामलें**						
राज्य	*वित्त वर्ष 2019-2020*		*वित्त वर्ष 2020-2021*		*वित्त वर्ष 2021-2022*	
	संख्या	*राशि*	*संख्या*	*राशि*	*संख्या*	*राशि*
असम	*5*	*2.02*	*1*	*0.11*	*2*	*4.59*

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आरबीआई को रिपोर्ट किए गए उधार धोखाधड़ी के मामले (ऋण धोखाधड़ी) शून्य है

उत्तर पूर्वी राज्यों की एसएमए (विशेष उल्लेख खाते) स्थिति:

(राशि करोड़ में)

राज्य	31.03.2021			31.03.2022		
	एसएमए-1	एसएमए-2	कुल एसएमए-1 + एसएमए-2	एसएमए-1	एसएमए-2	कुल एसएमए-1 + एसएमए-2
असम	1256	656	1912	856	197	1053
अरुणाचल प्रदेश	27	30	57	20	13	33
मणिपुर	198	73	271	151	11	162
मेघालय	43	19	63	25	9	34
मिजोरम	27	5	32	18	2	20
नागालैंड	12	12	24	12	3	15
त्रिपुरा	269	82	351	175	34	208
कुल योग	1831	878	2709	1257	269	1526

नए स्लिपेज की स्थिति: उत्तर पूर्वी राज्य

(राशि करोड़ में)

राज्य	नए स्लिपेज वित्त वर्ष 2020-21					नए स्लिपेज वित्त वर्ष 2021-22				
	कृषि	एमएसएमई	खुदरा	अन्य	कुल योग	कृषि	एमएसएमई	खुदरा	अन्य	कुल योग
असम	133	82	390	11	616	85	158	32	3	278
अरुणाचल	3	3	14	1	21	0	10	2	0	12

प्रदेश										
मणिपुर	8	8	25	1	42	5	21	8	0	34
मेघालय	0	3	2	0	5	1	8	1	0	11
मिजोरम	4	1	4	0	9	0	3	1	0	4
नागालैंड	0	1	3	0	5	1	4	1	0	6
त्रिपुरा	11	9	50	1	71	22	18	3	0	43
कुल योग	159	106	489	15	769	115	222	48	4	389

31.03.2021 को समाप्त पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान दबाव का स्तर कम हुआ है 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए नए एनपीए स्लिपेज जो 769 करोड़ रुपये थे, वह 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए घटकर 389 करोड़ रुपये हो गया साथ ही, कुल एसएमए-1+एसएमए-2 31.03.2021 के 2709 करोड़ रुपये से कम होकर 31.03.2022 को 1526 करोड़ रुपये हो गया है।

<u>यूको बैंक</u>

यूको बैंक, बैंक के मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक दिशानिर्देशों के दायरे में मानक उधार देने की प्रक्रिया का पालन करता है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद में पुनरुत्थान के प्रभाव के कारण, आर्थिक गतिविधि में एक गंभीर मंदी देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता के अनियमित नकदी प्रवाह के कारण, उधार खातों पर दबाव बढ़ गया है। हालाकिं, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 नियामक पैकेज की शुरुआत, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी (सीएलजीएस) योजना का कार्यान्वयन, संकल्प ढांचा 1.0 (आरएफ1.0) और संकल्प ढांचा 2.0 (आरएफ 2.0) आदि जैसे कई उपाय किए हैं, जिसके कारण उधार खातों को दबाव कम करने की प्रवृति में रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम के संबंध में दोनों संकल्प ढांचों का ब्यौरा निम्न है:-

(करोड़ रुपये में)

आर्थिक मंदी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था के कारण पुन:संरचित खातों की स्थिति						
विवरण	*कुल बैंक*		*पूर्वोत्तर राज्य*		*गुवाहाटी*	
	खाता	*राशि*	*खाता*	*राशि*	*खाता*	*राशि*
आरएफ 1.0	*2044*	*1332.38*	*76*	*19.63*	*35*	*13.61*
आरएफ 2.0	*50283*	*2834.80*	*6013*	*221.447*	*2982*	*119.08*

8. तत्पश्चात समिति ने यह जानना चाहा कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक द्वारा अपनी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या व्यापक उपाय किए जा रहे हैं, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया कि:-

<u>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u>

एसबीआई में हम डिजिटल उत्पादों में काफी निवेश कर रहें हैं और हम अपने एनालिटिक्स इंजनों के आधार पर ग्राहकों तक पहुँचने के लिए एनालिटिक्स का भी लाभ उठा रहे हैं। इससे ग्राहकों की मांग को समय पर और सबसे उपयुक्त तरीके से पूरा करने में मदद मिली है। हमने पहले ही कई डिजिटल चैनलों में प्रमुख बाज़ार हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

एसबीआई व्यवसाय को बढाने और क्रेडिट वृद्धि को हासिल करने के लिए अपने सह-उधार व्यवसाय को बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। बैंक कृषि और लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण के लिए सह-उधार साझेदारी करेगा और इन क्षेत्रों में स्लिपेज को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। देखने में आया है कि बही की गुणवता के मामले में सह-उधार भागीदारों को काफी अच्छा अनुभव प्राप्त है और हम इससे लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे कृषि पोर्टफोलियो में भी सुधर होगा।

एसबीआई ने अपनी अंडरराइटिंग प्रथाओं में भी काफी सुधार किया है और इसका विशुद्ध परिणाम यह है कि हम जोखिम का बेहतर आकलन करने की स्थिति में हैं। इसके अलावा, यदि कोई तनाव है, तो तनाव वास्तव में बैलेंस शीट बनाने से पहले ही ठीक कर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि तनाव के पहले के संकेतों की भी बहुत सावधानीपूर्वक निगरानी की जा रही है और बैलेंस शीट को भविष्य के किसी भी झटके से बचाने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>

लाभप्रदता और व्यवसाय में समग्र वृद्धि के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे ग्राहक सेवा और ग्राहक सुविधा सुनिश्चित करना, लीड जनरेशन पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और नये स्लिपेज को रोकना और वसूली पर ध्यान केंद्रित करना। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार और एबीपीआरएल की स्थापना ने कृषि (बांस की खेती) और एमएसएमई वित्तपोषण में अवसर खोले हैं। उपरोक्त के अलावा हमने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

<u>जमा:</u>

1. टैब और वीडियो केवाईसी जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने के माध्यम से उच्च कासा विकास को लक्ष्य किया जा रहा है।
2. विभिन्न ग्राहक वर्ग को लक्ष्य करने के लिए विविध उत्पाद लाना।
3. कासा उत्पादों की बिक्री के लिए मौजूदा विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं का लाभ उठाना।
4. मौजूदा भौगोलिक क्षेत्रों में रिटेल विक्रेताओं को जोड़ने के लिए सूक्ष्म बाजार वर्गीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना।
5. एकल नोडल खाते (एसएनए) के माध्यम से संस्थागत व्यवसाय प्राप्त करना।
6. सीएसी के माध्यम से कॉर्पोरेट वेतन खाते खोलना और कॉरपोरेट्स, एचएनआई और एनआरआई के साथ संबंधों को सशक्त बनाना।

7. सार्वजनिक उपक्रमों, शैक्षिक संस्थानों, ट्रस्टों, क्लबों और निगमों जैसे संस्थानों को लक्ष्य बनाने के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ टीम बनाकर अवसर का लाभ उठाना।

8. आरबीआई को डीईएएफ प्रेषण को कम करने के लिए निष्क्रिय/खोए हुए ग्राहकों को सक्रिय करना

<u>रैम अग्रिम:</u>

1. टाई-अप और सह-उधार के माध्यम से रैम पर ध्यान केन्द्रित करना।

2. टॉप अप ऋणों के लिए मल्टी चैनल लीड जनरेशन और विश्लेषण आधारित ऑफर।

3. कृषि बुनियादी ढांचे और संबद्ध कृषि गतिविधियों पर जोर।

4. कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बीसी नेटवर्क का लाभ उठाना; एसएचजी संचालित व्यवसाय।

5. कृषि स्वर्ण ऋण संवितरण को बढ़ाना।

6. क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को अपनाना।

7. मूल्य श्रृंखला आधारित उधार, चालान आधारित उधार और नकदी प्रवाह आधारित उधार पर ध्यान केन्द्रित करना।

8. चाय उत्पादक के वित्तपोषण पर विशेष जोर देते हुए इन क्षेत्रों में एक अच्छा व्यवसाय हासिल करने के लिए केसीसी (फसल), केसीसी (डेयरी), केसीसी (मत्स्य पालन) पीएमएफएमई, फार्म मशीनीकरण, गोदाम/कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, एसएचजी, संयुक्त देयता समूह(जेएलजी),किसान उत्पादक कम्पनियों(एफपीसी)/ संगठनो(एफपीओ) का वित्तपोषण के तहत कृषि ऋण प्रस्तावों का प्रभावी निपटान, चाय क्षेत्र में अच्छा व्यवसाय तैयार करने के लिए चाय किसानो पर विशेष बल।

9. इन क्षेत्रों को उधार देने पर कर्मचारियों का कौशल विकास।

10. कम एनपीए वाले विशिष्ट क्षेत्रों के उत्पादों को बढ़ावा देना।

11. प्रक्रिया दक्षता नियम-आधारित डिजिटलीकृत क्रेडिट अंडर-राइटिंग अपनाना।

आस्ति गुणवत्ता:

1. 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खातों पर विशेष ध्यान देने के साथ एनपीए खातों में वसूली।
2. छोटे एनपीए खातों का निपटान करने और लोक अदालतों में भागीदारी बढ़ाने के लिए मेगा ऋण मुक्ति शिविर।
3. सरफेसी का समय पर कार्यान्वयन और एनपीए खातों को एनएआरसीएल को हस्तांतरित करना।
4. ईडब्ल्यूएस का समय पर समाधान करना और बेहतर वसूली दक्षता के लिए ग्राहक व्यवहार अर्थात पुनर्भुगतान पैरामीटर का विश्लेषण करना।
5. बेहतर वसूली प्रयासों के लिए पीएनबी प्राइड ऐप का उपयोग करके स्वचालन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान केन्द्रीत करना।
6. ऋण में अंडर-राइटिंग मानकों में सुधार करके और दबावग्रस्त खातों में अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी करके नए स्लीपेज को कम करना।
7. विशेष ओटीएस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये तक के कृषि एनपीए में कमी।
8. ई-विक्रय गतिविधियों के समन्वयन के लिए मंडल सास्त्र स्तर पर नोडल अधिकारी को लाना।
9. एम-टच सहायता से ग्राहक की भागीदारी को सक्रिय करना।

डिजिटलीकरण:

1. नए ग्राहकों के पंजीकरण और सक्रियण के माध्यम से पीएनबी वन को बढ़ावा देने के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों को पीएनबी वन ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से लेनदेन करने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है।

2. सभी नए खातों में वैयक्तिक डेबिट कार्ड घर पर प्रदान कर डेबिट कार्ड को अपनाने और सक्रिय करने का अभियान।

3. डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन और पुरस्कार कार्यक्रमों का शुभारंभ।

4. पीएनबी कार्ड प्रस्तावों, पीएनबी वन के साथ साझेदारी के मूल्य वक्तव्य को रेखांकित करने के लिए संभावित भागीदारों के लिए पिचबुक बनाना।

5. एसटीपी और सहायता प्राप्त ऋण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना।

6. साझेदारी के माध्यम से ग्राहकों को अभी खरीदें बाद में भुगतान करें डिजिटल ऋण की पेशकश सुनिश्चित करना।

7. डिजिटलीकरण के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम (सीएफटी)।

8. डिजिटल कौशल और ज्ञान निर्माण के लिए कर्मचारी की भागीदारी को बढ़ाना।

<u>यूको बैंक</u>

यूको बैंक में किए गए प्रमुख बुनियादी सुधारों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

1. बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित निवल लाभ और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी शाखाओं को मासिक लाभ बजट आवंटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट बजट तैयार किया गया है। शाखाओं के लाभ की मासिक निगरानी से बैंक की लाभप्रदता में सुधार होगा।
2. गैर ब्याज आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बैंक ने कमीशन आय अर्जित करने के लिए विभिन्न तृतीय पक्ष बीमा उत्पादों के लिए कई बीमा संगठनों के साथ करार किया है।
3. बैंक के निवेश से अधिकतम आय अर्जित करने के अवसरों का पता लगाने के लिए मुंबई कोष (ट्रेजरी) शाखा द्वारा निरंतर उपाय किए जा रहे हैं।
4. बैंक ने गैर-ब्याज व्यय के तहत भी बजट आवंटित किया है ताकि परिचालन व्यय को कम करने के लिए गैर ब्याज व्यय विशेष रूप से नियंत्रणीय व्यय की प्रभावी निगरानी की जा सके।

5. *ऋण संस्कृति में बदलाव से आस्तियों की गुणवत्ता में मौलिक रूप से सुधार हुआ है। अग्रिमों पर बैंक की आय बढ़ाने के लिए रिटेल, कृषि और एमएसएमई अग्रिमों को मंजूरी देना प्राथमिकता है।*
6. *एकमुश्त निपटान में समय पर और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन एकमुश्त संपूर्ण निपटान प्लेटफॉर्म स्थापित और उपयोग किए गए हैं।*
7. *मजबूत स्तर पर एनपीए (अनर्जक आस्तियां) को नियंत्रित करने हेतु संकटपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए ऋण जोखिम प्रबंधन उपकरण और रणनीतियों को मजबूत किया जा रहा है। नए एनपीए होने से रोकने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के माध्यम से आस्तियों की विशेष निगरानी की जा रही है।*
8. *राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा मानकों का प्रवर्तन और लेखा परीक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करना।"*

9. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि विभिन्न व्यापक उपायों का क्या सकारात्मक प्रभाव देखा गया है, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी:-

<u>भारतीय स्टेट बैंक</u>

वित्त वर्ष 2022 के दौरान एसबीआई के प्रदर्शन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

- *कुल जमाओं में वर्ष दर वर्ष 10.06% की वृद्धि हुई। बचत बैंक जमाओं में वर्ष दर वर्ष 10.45% की वृद्धि हुई, जबकि सावधि जमाओं में वर्ष दर वर्ष 11.54% की वृद्धि हुई।*
- *कुल बैंक अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष 11.00% की वृद्धि हुई। घरेलू अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष 10.27% की वृद्धि दर्ज की गई जो मुख्यतः रिटेल व्यक्तिगत अग्रिमों (15.11% वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि से प्रेरित थी। विदेश कार्यालय अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष 15.42% की वृद्धि हुई।*
- *बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में 31,676 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है जो वित्त वर्ष 21 की तुलना में 55.19% अधिक है।*

- *परिसंपतियों पर आय 0.67% में वर्ष दर वर्ष 19 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई, जबकि आरओई 13.92% रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष दर वर्ष 398 आधार अंक की वृद्धि हुई है।*

- *सकल एनपीए अनुपात 101 आधार अंक कम होकर वर्ष दर वर्ष 3.97% रहा, जबकि शुद्ध अनुपात 48 आधार अंक कम होकर वर्ष दर वर्ष 1.02% रहा।*

- *वित्त वर्ष 22 के लिए स्लिपेज अनुपात 0.99% है, जो वित्त वर्ष 21 की तुलना में 19 आधार अंक कम है। वित्त वर्ष 22 के लिए क्रेडिट लागत मार्च 2021 तक 1.12% की तुलना में 0.55% रही है।*

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>

- *वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हमारे ईमानदार प्रयास के कारण बैंक व्यवसाय, परिसंपति गुणवत्ता और पूंजीकरण पर बेहतर प्रदर्शन दिखाने में सक्षम हुआ है। 31.03.22 तक पीएनबी 195 बीपीएस से 47.43% तक कासा शेयर में सुधार करने में सक्षम रहा है, सकल अग्रिम में 6.18% की वृद्धि दर्ज की गई है, सकल एनपीए% को 234 बीपीएस से घटाकर 11.78%, निवल एनपीए% को 93 बीपीएस से 4.80% तक कम किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में सीआरएआर को 18 बीपीएस बढ़ाकर 14.50% कर दिया।*

- *बैंक द्वारा सात राज्यों अर्थात असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इंफाल और अरुणाचल प्रदेश को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। असम राज्य में पंजाब नेशनल बैंक का कुल कारोबार कुल एससीबी का लगभग 10% है।*

- *इस क्षेत्र में 1 जोन और 8 सर्किल कार्यालय हैं, ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में और सरकारी विभाग के साथ संपर्क अच्छा है, जिसके परिणामस्वरूप कासा शेयर में वृद्धि हुई है।*

- *31.03.2022 तक असम राज्य में एमएसएमई (पीएस) सेगमेंट ओ/एस में पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी 14% है।*

यूको बैंक

- *हमारे बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक कुल 3,53,850.24 करोड़ रुपये का कारोबार किया।*
- *बैंक का 31 मार्च, 2022 तक 929.76 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है। और 31 मार्च, 2022 तक बैंक का परिचालन लाभ 15.63% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4797.43 करोड़ रुपये हो गया है।*
- *बैंक की शुद्ध ब्याज आय मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के 5479.70 करोड़ रुपये में 18.13% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2022 को बढ़कर 6472.95 करोड़ रुपये हो गया है।*
- *सकल एनपीए 31 मार्च, 2021 को 9.59% से घटकर 31 मार्च, 2022 तक 7.89% हो गया है और 31 मार्च, 2021 को निवल एनपीए 3.94% से घटकर 31 मार्च, 2022 तक 2.70% हो गया है।*
- *प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2022 तक बढ़कर 91.44% हो गया है।*
- *हमारे बैंक का 31 मार्च, 2022 तक बेसल-3 मानदंडों के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.74% और सीईटी- अनुपात 10.97% है।*

10. समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक के परिचालन लाभ, प्रावधान और निवल लाभ/हानि का विवरण जानने की इच्छा व्यक्त की। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी:-

भारतीय स्टेट बैंक

(करोड़ रुपए में)

विवरण	*वित्त वर्ष 2021*	*वित्त वर्ष 2022*
परिचालन लाभ	*71,554*	*75,292*
प्रावधान	*51,144*	*36,198*
निवल लाभ	*20,410*	*31,676*

पंजाब नेशनल बैंक

वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में पंजाब नेशनल बैंक का परिचालन लाभ, प्रावधान और निवल लाभ निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	*परिचालन लाभ*	*प्रावधान*	*निवल लाभ*
2020-21	*22,159*	*20,138*	*2,022*
2021-22	*20,761*	*17,304*	*3,457*

यूको बैंक

(करोड़ रुपए में)

विवरण	*वित्त वर्ष 2020-21*	*वित्त वर्ष 2021-22*
परिचालन लाभ	*4149.06*	*4797.43*
प्रावधान	*3982.03*	*3867.67*
निवल लाभ	*167.03*	*929.76*

11. समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम में ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में, निम्नानुसार जानकारी दी:-

भारतीय स्टेट बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक की सभी ऋण योजनाएं सम्पूर्ण भारत के ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं। कृषि, एमएसएमई, कॉरपोरेट और व्यक्तिगत खंड के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न उत्पाद और योजनाएं समाज के सभी वर्गों को शामिल करती हैं। ये योजनाएं और उत्पाद असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

- असम राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और संस्वीकृत ऋण राशि का ब्योरा निम्नवत है:-

पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान संस्वीकृत ऋण का ब्यौरा (असम राज्य)

(करोड़ रुपए में)

उत्पाद	2019-20		2020-21		2021-22	
	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि
परिसंपत्ति समर्थित ऋण (एबीएल)	29	30.67	48	44.37	61	55.85
ई डीएफएस	64	72.30	83	65.67	111	100.44
ई मुद्रा	77	0.37	442	2.04	638	3.05
ई स्मार्ट स्कोर	55	17.58	125	28.70	174	42.82
फ्लीट फ़ाइनांस	3	3.55	2	5.70	10	11.65
जीईसीएल (ईसीएलजीएस)	0	0.00	4978	302.20	101	36.14
एनयूएलएम	9	0.13	15	0.23	26	0.40
पीएबीएल	0	0.00	48	1.51	236	10.51
प्रधानमंत्री स्वनिधि	0	0.00	6454	6.45	9831	9.83
पीएमईजीपी	519	17.35	1027	40.30	986	40.15
एसएमई कार ऋण	5	0.40	8	2.46	10	1.19
एसएमई स्वर्ण ऋण	0	0.00	83	1.27	19	0.51
स्टैंड अप इंडिया ऋण	53	10.77	101	23.80	137	27.61
बैलेंस शीट वित्त पोषण व अन्य	7,110	541.43	4,541	454.18	4386	918.90

उप योग	7,924	694.55	17,955	978.88	16,726	1,259.05
केसीसी	19,315	144.24	18,790	140.96	13,761	114.90
एसएचजी	3,290	58.73	7,062	106.16	6,618	80.64
स्वर्ण ऋण	357	2.13	76	0.56	176	1.39
डेयरी ऋण	101	2.52	538	8.21	107	2.45
पोल्ट्री ऋण	35	0.90	140	1.90	264	7.57
मत्स्य ऋण	64	1.32	12	0.40	14	0.78
केसीसी (एएचएंडएफ)	0	0.00	363	2.34	348	2.82
एसीसी	42	0.35	9	6.06	2	22.40
अन्य कृषि ऋण	753	89.81	1765	13.09	3043	47.28
उप योग	23,957	300.00	28,755	279.68	24,333	280.23

(करोड़ रुपए में)

उत्पाद	2019-20		2020-21		2021-22	
	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि
आवास ऋण (सुरक्षा खाते सहित)	7,584	872.10	5845	721.02	5998	979.40
संपत्ति पर ऋण (एलएपी)	12	3.50	38	13.38	43	11.12
टॉप अप आवास ऋण	676	56.55	799	81.85	978	105.97
उप योग	8,272	932.15	6,682	816.25	7,019	1,096.49
ऑटो ऋण	13,312	693.14	14,370	790.65	14,792	888.96
शिक्षा ऋण	1,114	31.56	742	17.06	1043	27.44
एक्सप्रेस ऋण	1,08,632	4,472.96	1,35,286	6,321.87	1,39,343	7,754.98
पेंशन ऋण	25,824	605.24	39,256	921.65	43,496	1,269.23

स्वर्ण ऋण	178	1.91	1,893	19.79	1,381	15.93
जमा पर ऋण	4,458	120.33	5,241	131.24	5,404	143.47
अन्य व्यक्तिगत ऋण	5,833	25.02	2,176	26.75	8,683	70.65
उप योग	1,59,351	5,950.16	1,98,964	8,229.01	2,14,142	10,170.66
कुल	199504	7876.86	2,52,356	10,303.82	2,62,220	12,806.43

विगत 3 वित्त वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा (गुवाहाटी मंडल):

(करोड़ रुपए में)

उत्पाद	2019-20		2020-21		2021-22	
	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि
परिसंपत्ति समर्थित ऋण (एबीएल)	93	57.12	100	79.32	130	136.09
ई डीएफएस	71	95.01	111	101.83	163	153.86
ई मुद्रा	260	0.98	3463	16.03	2,114	10.18
ई स्मार्ट स्कोर	123	34.12	258	56.14	338	79.88
फ्लीट फाइनांस	3	3.95	2	5.70	11	12.56
जीईसीएल (ईसीएलजी एस)	0	0.00	9618	507.28	169	56.62
एनयूएलएम	113	1.85	148	2.36	187	3.13
पीएबीएल	0	0.00	75	2.38	379	17.17
प्रधानमंत्री स्वनिधि	0	0.00	10,981	10.98	11,463	11.46

पीएमईजीपी	1,914	60.78	2,755	98.56	2,565	96.14
एसएमई कार ऋण	7	1.25	12	3.00	15	1.49
एसएमई स्वर्ण ऋण	0	0.00	109	1.67	40	1.00
स्टैंड अप इंडिया ऋण	135	26.88	305	69.78	429	94.72
बैलेंस शीट वित्त पोषण व अन्य	10,403	978.24	9,464	1,058.68	9,014	2,707.30
उप योग	**13,122**	**1,260.18**	**37,401**	**2,013.71**	**27,017**	**3,381.60**
केसीसी	30,872	231.63	31,695	240.12	24,009	204.13
एसएचजी	3,472	62.27	7,919	118.53	7,888	99.49
स्वर्ण ऋण	978	9.60	766	10.54	1,588	21.42
डेयरी ऋण	129	3.81	558	8.71	145	3.39
पोल्ट्री ऋण	100	3.20	189	4.16	309	11.23
मत्स्य ऋण	169	3.91	575	10.57	804	18.12
केसीसी (एएचएंडएफ)	0	0.00	1,117	10.26	1,383	13.45
एसीसी	42	0.36	10	6.86	5	23.21
अन्य कृषि ऋण	1,312	127.00	2,295	18.58	7,040	114.58
उप योग	**37,074**	**441.78**	**45,124**	**428.33**	**43,171**	**509.02**

(करोड़ रुपए में)

उत्पाद	2019-20	2020-21	2021-22

	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि
आवास ऋण (सुरक्षा खाते सहित)	10,180	1,359.60	8,384	1,225.45	8,843	1,645.05
संपत्ति पर ऋण (एलएपी)	52	16.93	93	40.11	110	37.13
आवास ऋण टॉपअप	1,332	134.65	1,625	179.01	1,894	215.16
उप योग	**11,564**	**1,511.18**	**10,102**	**1,444.57**	**10,847**	**1,897.34**
ऑटो ऋण	21,627	1,175.17	23,374	1,344.55	22,690	1,408.99
शिक्षा ऋण	1,634	45.30	1,149	32.09	1,528	47.64
एक्सप्रेस क्रेडिट	2,04,842	8,877.97	2,51,905	12,214.27	2,54,090	14,806.04
पेंशन ऋण	43,533	1,032.00	61,755	1,458.31	67,673	1,966.10
स्वर्ण ऋण	364	3.88	2,768	31.97	2,149	28.54
जमा पर ऋण	7,077	228.35	7,482	229.25	7,653	258.41
अन्य व्यक्तिगत ऋण	9,874	59.31	3,529	48.98	11,236	109.99
उप योग	**2,88,951**	**11,421.98**	**3,51,962**	**1,53,59.42**	**3,67,019**	**18,625.71**
कुल	**3,50,711**	**14,635.12**	**4,44,589**	**19,246.03**	**4,48,054**	**24,413.67**

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>

पंजाब नेशनल बैंक ऐसी योजनाओं/उत्पादों का विस्तृत दायरा प्रदान करता है जो अखिल भारतीय स्तर पर ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप दबावग्रस्त एमएसएमई को होने वाली चुनौतियों/हानियों का मुकाबला करने के लिए एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी

बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं:-

- सरकार ने जीईसीएल, अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना, पीएम स्वनिधि, पीएमएमवाई, पीएमईजीपी, स्टैंड अप इंडिया और अग्रिमों के पुनर्गठन जैसी पहल की।
- कार्यशील पूंजी ऋणों का ई-नवीकरण, ऋण प्रबंधन प्रणाली पीएनबी लेन्स, Psbloansin59minutes.com ई-मुद्रा (शिशु) योजना जैसी डिजिटल पहल।
- नई स्कीमों/क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों का सरलीकरण/शुभारंभ।
- एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों की पहुंच बढ़ाना/विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से एमएसएमई योजनाओं का प्रचार करना।
- ये योजनाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/कमजोर वर्ग सहित समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं।
- जीबीबी, पीएलपी, एमसीसी और सीबीबी द्वारा विभिन्न विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बैम्बू क्लस्टर, हथकरघा आदि विभिन्न क्लस्टर को अपनाना।

<u>यूको बैंक</u>

यूको बैंक ने पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमएमवाई. पीएमईजीपी, केसीसी, एनआरएलएम, एनयूएलएम, पीएमएफएमई और स्टैंडअप इंडिया आदि जैसी सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू किया है।

सरकारी योजनाओं के अलावा, बैंक ने व्यावसायिक उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य योजनाओं को भी लागू किया है। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	योजना	उद्देश्य
1.	कृषि सावधि ऋण -अन्य	चाय बागानों का वित्तपोषण, शीत भंडारण का

		वित्तपोषण आदि।
2.	*यूको ट्रेडर*	*वित्तीय व्यापार गतिविधियों का वित्तपोषण*
3.	*यूको उद्योग बंधु*	*विनिर्माण और सेवा इकाइयों का वित्तपोषण*
4.	*यूको वाणिज्यिक वाहन*	*वाणिज्यिक वाहनों का वित्तपोषण*

12. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम में, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक सरकार की विभिन्न क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया के तहत ऋण प्रदान करते हैं, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:-

<u>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u>

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, डीएवाई-एनयूएलएम, डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमएमवाई और एसयूआई के तहत सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष रूप से असम में ऋण प्रदान किए जाते हैं।

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>

पंजाब नेशनल बैंक के पास सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, पीएमएमवाई और स्टैंडअप इंडिया सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं की गतिविधियों के लिए उत्पादों/योजनाओं की प्रचुरता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ कमजोर वर्ग सहित समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएं तैयार की गई है।

उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से असम में सरकार के नेतृत्व वाली पहल के तहत बैंक की प्रमुख क्रेडिट अंडर-राइटिंग है।

वित्त वर्ष 2021-22 में खाते और अनुमोदित राशि की मंजूरी की संख्या:

(राशि करोड़ में)

राज्य	माइक्रो		लघु		मध्यम	
	खातों की संख्या	मंजूरी	खातों की संख्या	मंजूरी	खातों की संख्या	मंजूरी
अरुणाचल प्रदेश	47	3	6	0	0	0
असम	10744	245	541	126	113	52
मणिपुर	721	16	24	3	1	0
मेघालय	217	6	42	1	2	1
मिजोरम	89	5	4	0	0	0
नागालैंड	128	7	19	2	0	0
सिक्किम	190	13	30	4	4	0
त्रिपुरा	1905	70	273	23	39	15
पूर्वोत्तर (राज्यों) का योग	14041	364	939	158	159	69
सम्पूर्ण पैन इंडिया के रूप में पीएनबी	176963	9669	24147	9334	4106	9111

वित्त वर्ष 2021-22 में जीईसीएल संस्वीकृति, पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी, पीएमएमवाई और स्टैन्ड-अप इंडिया:

(राशि करोड़ में)

राज्य	जीईसीएल स्वीकृति	पीएम स्वनिधि	पीएमईजीपी (आरआरबी सहित)	पीएमईजीप (वित्त वर्ष	स्टैन्ड-अप इंडिया

					(वित्त वर्ष 2021-22)		2021-22)		(वित्त वर्ष 2021-22)	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
अरुणाचल प्रदेश	61	433.16	18	0.02	107	5.98	9	0.89	1	0.32
असम	7913	137.71	8385	9.00	27289	670.95	614	41.70	32	12.18
मणिपुर	224	7.50	873	0.88	4984	72.82	159	14.00	15	4.38
मेघालय	225	7.04	17	0.02	618	10.76	4	0.25	15	2.48
मिजोरम	65	4.59	0	0.00	208	10.06	13	1.21	6	1.00
नागालैंड	73	1.86	21	0.02	160	8.10	55	5.92	3	0.49
सिक्किम	156	6.73	0	0.00	329	17.52	8	0.69	1	0.12
त्रिपुरा	1143	38.35	799	0.85	19526	333.22	174	12.65	24	4.08
पूर्वोत्तर (राज्यों) का योग	9860	637	10113	11	53221	1129	1036	77	97	25
सम्पूर्ण पैन इंडिया के रूप में पीएनबी	240127	20616	234324	244	659508	16843	10040	914	285	58

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (दैनिक-एनयूएलएम) वित्त वर्ष 2021-22: एसएचजी के संबंध में पीएनबी की स्थिति:-

(राशि लाख में)

राज्य	संवितरण (1)		महिला स्वयं सहायता समूहों में से (1)		31.03.22 तक बकाया राशि		महिला स्वयं सहायता समूहों में से (2)	
	खातों की संख्या	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वितरित राशि	खातों की संख्या	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वितरित राशि	खातों की संख्या	31.03.22 तक बकाया राशि	खातों की संख्या	31.03.22 तक बकाया राशि
अरुणाचल प्रदेश	शून्य							
असम	80	173	24	26	2211	1970	663	394
मणिपुर	57	20	17	3	94	41	28	8
मेघालय	21	0	6	0	32	13	10	3
मिजोरम	51	17	15	3	58	47	17	9
नागालैंड	0	0	0	0	21	10	6	2
सिक्किम	1	1	0	0	7	10	2	2
त्रिपुरा	200	35	60	5	1540	892	462	178
पूर्वोत्तर (राज्यों) का योग	410	246	122	37	3963	2983	1188	596
सम्पूर्ण पैन इंडिया के रूप में पीएनबी	28241	16792	8472	2519	38241	34658	11472	6932

नोट: दिव्यांग एसएचजी, सड़क विक्रेता एसएचजी, कूड़ा बीनने वाले एसएचजी और स्वच्छता कार्यकर्ता एसएचजी से संबंधित डेटा को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (दैनिक-एनआरएलएम) वित्त वर्ष 2021-22: एसएचजी के संबंध में पीएनबी की स्थिति:

(राशि लाख में)

राज्य	संवितरण		31.03.22 तक बकाया राशि	
	खातों की संख्या	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वितरित राशि	खातों की संख्या	31.03.22 तक बकाया राशि
अरुणाचल प्रदेश	4	6	93	89
असम	7978	12357	11813	15941
मणिपुर	40	60	278	148
मेघालय	11	24	17	28
मिजोरम	2	0	14	15
नागालैंड	1	8	10	21
सिक्किम	3	6	14	5
त्रिपुरा	1150	2925	3280	2260
पूर्वोत्तर (राज्यों) का योग	9189	15386	15519	18507
सम्पूर्ण पैन इंडिया के रूप में पीएनबी	208977	425638	362395	452248

<u>यूको बैंक</u>

यूको बैंक पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी, डीएवाई-एनयूएलएम, डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमएमवाई और स्टैंड-अप इंडिया आदि जैसी विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करता है।

13. तत्पश्चात, समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम में पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किए गए कुल लाभार्थियों की संख्या जानना चाहा। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:-

<u>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u>

पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान विभिन्न उत्पादों/योजनाओं के माध्यम से स्वीकृत ऋण का ब्यौरा (असम राज्य):

(राशि करोड़ में)

वित्त वर्ष *2019-20*		वित्त वर्ष *2020-21*		वित्त वर्ष *2021-22*	
खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
1,99,504	*7,876.86*	*2,52,356*	*10,303.82*	*2,62,220*	*12,806.43*

पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान विभिन्न उत्पादों/योजनाओं के माध्यम से स्वीकृत ऋण का ब्यौरा (गुवाहाटी सर्किल):

(राशि करोड़ में)

वित्त वर्ष *2019-20*		वित्त वर्ष *2020-21*		वित्त वर्ष *2021-22*	
खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
3,50,711	*14,635.12*	*4,44,589*	*19,246.03*	*4,48,054*	*24,413.67*

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>

वर्ष-वार जानकारी इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष	*पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की संख्या*	*असम राज्य*
2019-20	*24,105*	*19,056*

2020-21	*21,002*	*15,599*
2021-22	*14,442*	*10,971*

यूको बैंक

(i) पीएमईजीपी योजना के तहत कार्य निष्पादन:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2019-20		2020-21		2021-22	
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि
असम	**206**	**3.07**	**182**	**2.82**	**119**	**1.45**
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	1	0.24	4	0.14
मणिपुर	8	0.16	18	0.49	6	0.10
मेघालय	2	0.02	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	22	0.35	15	0.26	2	0.03
नागालैंड	15	0.71	18	0.96	25	0.59
त्रिपुरा	22	0.42	17	0.35	20	0.23
कुल	**275**	**4.73**	**251**	**5.12**	**176**	**2.54**

कम संस्वीकृति के कारण:

- *कुछ उदाहरणों में ऐसा पाया गया है कि ग्राहकों ने उसी इकाई पर ऋण के लिए आवेदन किया है जो पहले से ही अन्य उधारदाताओं द्वारा वित्तपोषित है।*
- *सिबिल चूक /खराब सिबिल स्कोर।*
- *लाभार्थियों ने ऋण की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर साझा नहीं किए।*

(ii) स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत कार्यनिष्पादन:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		प्रारंभ से कुल	
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि
असम	26	6.24	33	6.99	13	3.77	143	32.75
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.30
मणिपुर	6	1.19	0	0.00	1	0.15	22	4.54
मेघालय	2	0.34	1	0.30	1	0.15	6	2.27
मिजोरम	11	5.18	7	2.60	1	0.12	28	11.92
नागालैंड	9	3.28	8	4.10	4	1.60	28	11.29
त्रिपुरा	4	0.80	6	1.00	3	1.16	28	5.63
कुल	58	17.03	55	14.99	23	6.95	256	68.70

(iii) <u>पीएमएमवाई योजना के तहत कार्यनिष्पादन:</u>

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2019-20			2020-21			2021-22		
	लक्ष्य	संस्वीकृति	% प्राप्ति	लक्ष्य	संस्वीकृति	% प्राप्ति	लक्ष्य	संस्वीकृति	% प्राप्ति
असम	149	239	160 %	140	158.00	113%	152	297	195 %
अरुणाचल प्रदेश	2	0.42	21%	2	1.33	67%	2	0.31	16%
मणिपुर	14	10.00	71%	12	12	100%	12	11	92%
मेघालय	8	4	50%	7	4	57%	8	4	50%
मिजोरम	3	5	167 %	2	7	350 %	2	2.44	122 %
नागालैंड	7	7	100 %	7	8	114%	6	7	117 %
त्रिपुरा	31	18	58%	26	36	138%	24	29	121 %

कुल	214	283.42	132 %	196	226.33	115%	206	350.75	170 %

(iv) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कार्यनिष्पादन:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021 22	
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि
अरुणाचल प्रदेश			1	0.02	1	0.02
असम	363	182	405	299.22	436	430.13
मणिपुर	12	1.17	13	1.36	18	1.86
मेघालय	4	0.12	4	0.07	4	0.05
मिजोरम	4	0.18	4	0.16	4	0.14
नागालैंड	9	0.49	8	0.49	10	0.62
सिक्किम	4	0.10	4	0.19	4	0.19
त्रिपुरा	26	4.02	38	5.79	52	7.75
कुल	422	188.20	477	307.29	529	440.75

(v) डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कार्यनिष्पादन:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021 22	
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि
अरुणाचल प्रदेश			1	0.02	1	0.02
असम	19	1.04	43	6.38	62	12.35
मणिपुर					4	0.21
मेघालय						

मिजोरम						
नागालैंड	*2*	*0.09*	*2*	*0.15*	*4*	*0.30*
सिक्किम			*1*	*0.02*	*1*	*0.02*
त्रिपुरा	*4*	*0.06*	*6*	*0.14*	*17*	*0.86*
कुल	***25***	***1.19***	***53***	***6.71***	***89***	***13.76***

14. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जिसे सरकार द्वारा 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर एमएसएमई सहित व्यवसायों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करना था, के बारे में बताते हुए समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से असम में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक प्रदर्शन पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

<u>भारतीय स्टेट बैंक</u>

पूर्वोत्तर राज्यों में 01.05.2020 से 30.04.2022 तक ईसीएलजीएस योजना के तहत निष्पादन निम्नानुसार है: –

(करोड़ रुपये में)

	संख्या	*संख्या*	*राशि*	*राशि*
राज्य	*संचयी संस्वीकृत*	*संचयी संवितरण*	*संचयी संस्वीकृत*	*संचयी संवितरण*
अरुणाचल प्रदेश	*858*	*358*	*28.40*	*21.86*
असम	*10,832*	*5,709*	*814.84*	*557.99*
मणिपुर	*1,369*	*704*	*38.99*	*28.75*
मेघालय	*2,571*	*1,640*	*140.06*	*96.74*
मिजोरम	*1,724*	*1,405*	*29.55*	*29.27*
नागालैंड	*1,365*	*1,014*	*35.82*	*20.81*

त्रिपुरा	2,253	1,183	65.61	54.83
कुल	20,972	12,013	1,153.26	810.24

पंजाब नेशनल बैंक

बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप दबावग्रस्त एमएसएमई द्वारा झेली गई चुनौतियों/नुकसान का सामना करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करना। जीईसीएल का लाभ देने के लिए, पात्र उधारकर्ताओं को पूर्व-अनुमोदित ऋण के लिए एसएमएस और ई-मेल भेजे गए थे, ग्राहकों के लिए रेडी रेकनर के रूप में कॉर्पोरेट वेबसाइट पर योजना को अपडेट करने के साथ-साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इस योजना का प्रचार किया गया था।

इस योजना के तहत निष्पादन निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीईसीएल स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या	असम राज्य
2019-20*	शून्य	शून्य
2020-21	7,660	6,193
2021-22	2,199	1,719

* यह योजना 27.05.2020 को शुरू की गई थी।

यूको बैंक

यूको बैंक ने असम राज्य में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) सुविधा के तहत 9,928 लाभार्थियों को अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 संकट के कारण विपत्ति के मद्देनजर व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 106 करोड़ रुपये की सुविधा प्रदान किया है।

(करोड़ रुपये में)

राज्य	संस्वीकृत	
	खातों की संख्या	राशि
अरुणाचल प्रदेश	84	0.70
असम	9,928	106.28
मणिपुर	1,027	3.17
मेघालय	159	1.56
मिजोरम	305	5.88
नागालैंड	440	3.10
त्रिपुरा	1,498	19.02
कुल	13,441	139.71

15. समिति द्वारा स्पष्ट रूप से पूछताछ किए जाने पर कि क्या भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से असम में बड़े पैमाने पर लोगों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने में कोई भेदभाव किया जाता है और क्या इस संबंध में इन बैंकों के पास कोई सूचना/ शिकायत उपलब्ध है, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

भारतीय स्टेट बैंक

कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक को समाज के हर वर्ग को कवर करते हुए अपनी व्यापक पहुंच और विविध प्रस्तावों पर गर्व है।

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक राज्यों/क्षेत्रों के आधार पर भेदभाव किए बिना उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है। बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों/फीडबैक से निपटने के लिए समर्पित कस्टमर केयर सेल है और हमारा उच्च प्रयास है कि उधारकर्ताओं से संबंधित किसी भी शिकायत या जानकारी को समय पर निपटाया जाए और इष्टतम समाधान प्रदान किया जाए।

यूको बैंक

यूको बैंक असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर लोगों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने में भेदभाव नहीं करता है। हालांकि, हमें पिछले तीन वर्षों में पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका समाधान कर दिया गया है।

टिप्पणियां/सिफारिशें

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन प्रमुख बैंकों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक के संबंध में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए)

16. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के आलोक में विशेष रूप से गुवाहाटी में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक की ऋण योजनाओं के बारे में ग्राहकों की धारणा और प्रभावशीलता के बारे में श्री फणी धर दास के अभ्यावेदन की विस्तृत जांच करने के बाद समिति ने नोट किया है कि एसबीआई के मामले में असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनपीए स्तरों में निरपेक्ष रूप से मामूली वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कुल एनपीए 1759 करोड़ रुपये हो गया जोकि 31 मार्च 2021 को 1730 करोड़ रुपये था। हालांकि, वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021-22 के दौरान ऋण में वृद्धि के बावजूद, खुदरा पोर्टफोलियो में अग्रिमों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल एनपीए प्रतिशत 3.51% से घटकर 3% हो गया है, जबकि पीएनबी के मामले में विशेष उल्लेख खातों (एसएमए-1 और एसएमए-2) की कुल संख्या पूर्वोत्तर राज्यों में 2709 (31.03.2022 को) से घटकर 1526 (31.03.2021 को) हो गई है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में कृषि, एमएसएमई, खुदरा और अन्य क्षेत्रों में बैंक की फ्रेश स्लिपेज/एनपीए स्लिपेज स्थिति के संबंध में, यह स्पष्ट है कि स्ट्रेस लेवल 769 करोड़ रुपये (31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए) से घटकर 389 करोड़ रुपये (31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए) हो गया है। यूको बैंक के संबंध में, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण उधार खातों का स्ट्रेस बढ़ गया था, वर्तमान में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 नियामक पैकेज की शुरूआत, ईसीएलजीएस योजना, रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 (आरएफ 1.0) और रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 (आरएफ 2.0) आदि के कार्यान्वयन जैसे कई उपायों के कारण कम हो रहा है।

17. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के तीन प्रमुख बैंकों अर्थात एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक के संबंध में एनपीए स्तरों के सांख्यिकीय विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच के

आधार पर समिति को ज्ञात हुआ कि स्ट्रेस में वृद्धि मुख्य रूप से कोविड-19 व्यवधान के कारण आर्थिक कार्यकलापों की धीमी गति और परिणामस्वरूप आय में गिरावट के कारण हुई है जिसने लेनदारों की पुनर्भुगतान क्षमता को प्रभावित किया है। हालांकि, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और इन पीएसबी के प्रबंधन द्वारा परिचालन प्रयासों के कारण हाल के दिनों में महामारी के स्तर में ढील के साथ बैंकों के एनपीए स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है। उपर्युक्त के बावजूद, समिति इन पीएसबीएस के प्रबंधन को ऋणों की मंजूरी का पेशेवर प्रबंधन करने और उनके द्वारा संवितरित ऋणों पर दबाव के शुरुआती संकेतों को नोटिस करने के लिए अपने स्वयं के अनूठे और अभिनव निगरानी तंत्र तैयार करने के लिए आगाह करना चाहेगी ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। इस अगली कड़ी में समिति का यह भी विचार है कि संदर्भाधीन इन पीएसबी को अपने संकल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बैड लोन/स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है, जिससे उनकी बैलेंस शीट नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो सके और एक मजबूत, सक्रिय और प्रभावी पर्यवेक्षी तंत्र स्थापित करके उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके जिससे उनकी समग्र पूंजी स्थिति मजबूत होगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को भारतीय रिजर्व बैंक और इन पीएसबीएस के प्रबंधन के समन्वय से एनपीए की घटती प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए सभी आवश्यक और उचित उपाय करने चाहिए, जिससे इन पीएसबीएस को नए निवेश के लिए ऋण प्रदान करने के अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने तथा अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए अपने कार्यकलापों में सुधार हो। इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक द्वारा अपनी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदम

18. तत्काल अभ्यावेदन की जांच के दौरान, समिति को वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक द्वारा सूचित किया गया कि ये तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभकारिता और व्यवसायों में समग्र वृद्धि के लिए डिजिटाइजेशन, को-लैंडिंग प्रथाओं, परिसंपत्तियों और जोखिमों के शीघ्र और प्रभावी मूल्यांकन आदि को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं

जिससे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। एसबीआई के संबंध में, बैंक डिजिटाइजेशन में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है जिससे यह कई डिजिटल चैनलों में प्रमुख बाजार हिस्सेदारी हासिल करने वाले अपने विश्लेषणात्मक इंजनों के आधार पर ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इसने ग्राहकों की मांग को समय पर और उचित तरीके से पूरा करने में भी मदद की है। समिति को यह भी बताया गया कि एसबीआई कृषि तथा लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण के लिए को-लेंडिंग साझेदारी में प्रवेश करते हुए व्यवसाय को बढ़ाने और ऋण वृद्धि का लाभ उठाने के लिए अपने को-लेंडिंग व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्लिपेज को कम करना है। इसके अलावा, एसबीआई अपनी हामीदारी प्रथाओं को भी काफी मजबूत कर रहा है जिसने इसे भविष्य के किसी भी शॉक से बैलेंस शीट को बचाने के लिए उचित कार्रवाई करके बेहतर तरीके से जोखिम का आकलन और निगरानी करने में सक्षम बनाया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी विभिन्न कदम उठाए हैं, अर्थात् ग्राहक सेवा और ग्राहक सुविधा सुनिश्चित करना, लीड जनरेशन पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और फ्रेश स्लिपेज को रोकना और बैंक की लाभप्रदता और व्यवसायों में समग्र वृद्धि के लिए वसूली पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा, बैंक ने जमा में वृद्धि, रैम अग्रिमों की स्थिति में सुधार, परिसंपत्ति गुणवत्ता की निगरानी और डिजिटाइजेशन आदि के लिए अन्य पहलें भी की है। इसी तरह, यूको बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के अनुमानित शुद्ध लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट बजट तैयार करने, नॉन-इंटरेस्ट इंकम बढ़ाने, नॉन-इंटरेस्ट व्यय के तहत बजट के आवंटन, क्रेडिट संस्कृति में बदलाव, एकमुश्त निपटान में समय पर और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के माध्यम से परिसंपत्तियों की विशेष निगरानी और ऑडिटिंग मानकों के प्रवर्तन और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे प्रमुख सुधार किए हैं।

19. सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों अर्थात एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक द्वारा अपनी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए जा रहे उपरोक्त उपायों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पाया कि उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप एसबीआई अपनी कुल जमा राशि, संपूर्ण बैंक अग्रिम, परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी वाईओवाई तथा शुद्ध लाभ में वृद्धि करने में सक्षम रहा है, जबकि, सकल और शुद्ध एनपीए अनुपात वाईओवाई में कमी आई है। जहां तक

पीएनबी का संबंध है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक व्यवसाय, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजीकरण पर बेहतर प्रदर्शन दिखाने में सक्षम रहा है। 31.03.22 की स्थिति के अनुसार, पीएनबी अपनी सीएएसए हिस्सेदारी 195 बीपीएस से बढ़ाकर 47.43 प्रतिशत करने में सफल रहा है। इसने सकल अग्रिमों में 6.18% की वृद्धि दर्ज की है और सकल एनपीए% को 234 बीपीएस घटाकर 11.78% कर दिया है, जबकि, शुद्ध एनपीए% 93 बीपीएस से घटकर 4.80% हो गया है। इसने सीआरएआर को पिछले वर्ष की तुलना में 18 बीपीएस बढ़ाकर 14.50% कर दिया है। यूको बैंक ने अपने नेट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि दर्ज की है और 2021 से 2022 तक अपनी शुद्ध ब्याज आय में 18.13% की वृद्धि करने में भी सक्षम रहा है। इसके अलावा, बैंक वित्त वर्ष 2021 से 2022 तक अपने जीएनपीए और शुद्ध एनपीए को क्रमशः 9.59% से घटाकर 7.89% और 3.94% से 2.70% करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा, इसने प्रोविजन कवरेज रेशियो (पीसीआर) को 31.03.2022 तक बढ़ाकर 91.44% कर दिया है।

20. समिति भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक द्वारा अपनी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों से संतुष्ट है। तथापि, प्रतिस्पर्धी वित्तीय बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को प्रतिस्पर्धी तरीके से अपने समग्र वित्तीय कार्यकलापों को री-कैलिब्रेट करना चाहिए जिसके लिए यह आवश्यक है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों का पालन करें। इसके बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनकी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए मौजूदा रणनीतियों और उपायों के अलावा परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रबंधन दक्षता के संदर्भ में सुधार की हमेशा गुंजाइश रही है। समिति की राय है कि, बैंकिंग संस्थानों को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार निष्पादन ग्रिड को 'मास्टर तकनीक' के रूप में अपनाना चाहिए जो एक तरफ तो सेवाओं का इष्टतम उपयोग करेगा और दूसरी ओर, बैंकों की तकनीकी औपचारिकताओं की तुलना में सेवाओं के साथ पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के प्रतिधारण को प्रोत्साहित करेगा। इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते समय जवाबदेही, आश्वासन और सहानुभूति पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को सुरक्षित बैंकिंग प्रचालनों के लिए प्रभावी और कुशल सुरक्षा प्रणालियां सुनिश्चित करनी चाहिए और सेवा की गुणवत्ता के बारे में ग्राहकों की धारणा को बढ़ाना चाहिए। इस संबंध में समिति की

इच्छा है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक के प्रबंधन के समन्वय से ग्राहक सेवा और सुविधा से संबंधित उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न उपायों और सुधारों पर काम करने के लिए अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करे ताकि निकट भविष्य में इनका प्रभाव दिखाई दे। इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड योजनाएं पेश करने में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक का कार्य-निष्पादन

21. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर समिति नोट करती है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कृषि, एमएसएमई, कॉरपोरेट और व्यक्तिगत खंडों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं और उत्पादों की पेशकश कर रहा है, जिससे उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों के ग्राहकों सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जा रहा है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। इस संबंध में, समिति ने नोट किया कि एसबीआई के मामले में, विभिन्न प्रकार की क्रेडिट योजनाओं और उत्पादों के तहत खातों की संख्या 3,50,711 थी, जिसके माध्यम से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 14,635.12 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 4,44,589 ऋण खातों के माध्यम से, 19,246.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 4,48,054 ऋण खातों के माध्यम से, उत्तर-पूर्वी राज्यों (गुवाहाटी सर्कल) में 24,413.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। असम राज्य में ऐसे ऋण खातों की संख्या 1,99,504 थी, जिनमें वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 7,876.86 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 2,52,356 ऋण खातों हेतु 10,303.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 2,62,220 ऋण खातों में 12,806.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। जहां तक पीएनबी का संबंध है, बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप दबावग्रस्त एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियों/हानियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, अर्थात, एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद

करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। पीएनबी जीईसीएल, अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, पीएम स्व-निधि, पीएमएमवाई, पीएमईजीपी, स्टैंड अप इंडिया और अग्रिमों की पुनर्संरचना जैसी सरकार द्वारा शुरू ली गई पहलों के अलावा कार्यशील पूंजी ऋणों के ई-नवीकरण, ऋण प्रबंधन प्रणाली पीएनबी लैंस, PSBloansin59minutes.com ई-मुद्रा (शिशु) योजना जैसी डिजिटल पहलों को प्रस्तावित कर रहा है। इसके अलावा, पीएनबी ने जीबीबीएस, पीएलपी, एमसीसी और सीबीबी के माध्यम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ-साथ विभिन्न क्लस्टरों, जैसे बांस क्लस्टर, हथकरघा आदि को अपनाया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएनबी ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 24,105 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया है, जबकि असम राज्य में लाभार्थियों की संख्या 19,056 थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या 21,002 थी और असम में, यह 15,559 थी और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 14,442 लाभार्थियों और असम के 10,971 लाभार्थियों को पीएनबी द्वारा ऋण प्रदान किया गया था। समिति ने आगे नोट किया कि यूको बैंक ने उत्तर-पूर्व राज्यों में पीएमएमवाई, पीएमईजीपी, केसीसी, एनआरएलएम, एनयूएलएम, पीएमएफएमई और स्टैंड-अप इंडिया आदि जैसी विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा, यूको बैंक ने व्यावसायिक उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य स्कीमें भी कार्यान्वित की हैं जैसे चाय बागान और शीत भंडारण वित्तपोषण के लिए कृषि सावधि ऋण इत्यादि, व्यापार गतिविधि के वित्तपोषण के लिए यूको ट्रेडर, विनिर्माण और सेवा इकाइयों के वित्तपोषण के लिए यूको उद्योग बंधु और वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए यूको वाणिज्यिक वाहन।

22. उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विभिन्न क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं और उत्पादों की पेशकश करने में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति यह उल्लेख करना चाहती है कि सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं और उत्पादों के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करने के तरीकों और साधनों को तैयार करते समय भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, व्यावसायिक और सांस्कृतिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन पीएसबीएस के प्रबंधन को वित्तीय समावेशन के भाग के रूप में ग्राहकों की सुविधा के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र के दूरदराज के हिस्सों में बैंक शाखाओं/सेवाओं के विस्तार की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए, क्योंकि बैंक खाता प्राथमिक आवश्यकता है जो किसी भी

बैंकिंग सेवा या उत्पाद और ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, चूंकि बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और उत्पादों के बारे में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों को पता नहीं होता है, इसलिए बैंक प्रबंधन को नियमित रूप से विभिन्न विज्ञापन वाहनों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने निरंतर प्रयास करने चाहिए ताकि आम जनता इन योजनाओं के बारे में जागरूक हो सके। इस क्रम में, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) यह सुनिश्चित करे कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक द्वारा पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार प्रायोजित सभी योजनाएं और उत्पाद प्रस्तावित किए जाएं ताकि वे प्रभावी कार्यान्वयन के साथ वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर इस संबंध में तैयार की जाने वाली नवीनीकृत कार्यनीति से अवगत होना चाहती है।

उत्तर-पूर्व राज्यों विशेषकर असम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं की पेशकश करने में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक का कार्य-निष्पादन।

23. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर, समिति ने नोट किया कि संदर्भाधीन तीन पीएसबीएस, उत्तर-पूर्व राज्यों और विशेषरूप से असम में पीएमईजीपी, डीएवाई-एनयूएलएम, डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमएमवाई और स्टैंड अप इंडिया जैसी सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराते रहे हैं।

24. तथापि, समिति इस बात को प्रकाश में लाना चाहती है कि पीएमईजीपी, डीएवाई-एनयूएलएम, डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमएमवाई और स्टैंड अप इंडिया जैसी सरकारी योजनाएं देश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन को सुगम बनाने और एमएसएमई के

संवर्धन और विकास हेतु जो वित्त तक पहुंच में सुधार करके विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में शामिल हैं, की प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा, ये योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, देश में रोजगार की कमी थी और विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों ने अपनी आजीविका खो दी थी। इसके अलावा, एससी, एसटी और कमजोर वर्ग जो समाज के असहाय वर्ग हैं, महामारी के कारण वित्तीय संकट से ग्रस्त थे। ऐसे परिदृश्य में, समिति का सुविचारित मत है कि उपर्युक्त फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से एमएसएमई क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पुनरुत्थान हो सकता है, जिससे सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को पूरा किया जा सकता है। इसलिए समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि सरकार की उपरोक्त सभी फ्लैगशिप योजनाओं को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए ताकि देश के कार्यबल को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हेतु इन योजनाओं के तहत आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति सभा में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर इन पीएसबीएस द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत होना चाहेगी।

कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की पेशकश करने में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक का कार्य-निष्पादन।

25. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए सांख्यिकीय ब्यौरों के आधार पर समिति ने नोट किया है कि संदर्भाधीन तीन पीएसबी अर्थात एसबीआई, पीएनबी और यूको बैंक ने उत्तर-पूर्व राज्यों में ईसीएलजीएस योजना के तहत ऋण वितरित किए हैं। एसबीआई ने उत्तर-पूर्व राज्यों में संचयी रूप से 01.05.2020 से 30.04.2022 तक 20,972 खातों (1,152.26 करोड़ रुपये) को स्वीकृति दी है, जिसके तहत 12,013 खातों के माध्यम से 810.24 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। पीएनबी के संबंध में, वर्ष 2020-21 में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कुल 7,660 लाभार्थियों (असम राज्य में 6,193

लाभार्थियों) को जीईसीएल को मंजूरी दी गई थी। इसी तरह, वर्ष 2021-22 में, पीएनबी ने जीईसीएल योजना के तहत 2,199 लाभार्थियों (असम राज्य में 1,719 लाभार्थियों) को स्वीकृति दी थी। इसके अलावा, यूको बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए ईसीएलजीएस सुविधा के तहत 13,441 लाभार्थियों को 139.71 करोड़ रुपये (असम के 9928 लाभार्थियों को 106.28 करोड़ रुपये की राशि) के लाभ प्रदान किए थे।

26. समिति उत्तर-पूर्व राज्यों में ईसीएलजीएस योजना के तहत स्वीकृत राशि और संवितरण के खराब अनुपात को नोट करते हुए बाध्य है, विशेषकर उस समय जब एमएसएमई क्षेत्र अपना अस्तित्व बचाने और फिर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने और नकदी की कमी के कारण परिचालन में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसलिए, समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक को मौजूदा उधमों को ऋण सहायता के माध्यम से उत्तर-पूर्व राज्यों में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए ईसीएलजीएस योजना के तहत ऋणों के संवितरण के माध्यम से आवंटित निधियों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली;

12 दिसंबर, 2022

21 अग्रहायण, 1944(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति

गोपनीय

याचिका समिति की पच्चीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

याचिका समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की पच्चीसवीं बैठक सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को दोपहर 1500 बजे से 1700 बजे तक, समिति कक्ष 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध (विस्तार), नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री हरीश द्विवेदी - अध्यक्ष

सदस्य

2. **श्री एंटो एन्टोनी**
3. **श्री हनुमान बेनीवाल**
4. **श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक**
5. **डॉ जयंत कुमार रॉय**
6. **श्री अरविन्द सावंत**
7. **श्री बृजेन्द्र सिंह**
8. **श्री सुनील कुमार सिंह**

सचिवालय

1. **श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव**
2. **श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक**

2. प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने निम्न प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विचार किया:-

(i) *** *** *** *** *** ***

(ii) *** *** *** *** *** ***

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से गुवाहाटी में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक की ऋण योजनाओं की ग्राहकों की धारणा और प्रभावशीलता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री फणी धर दास से प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिवेदन;

(iv)	***	***	***	***	***	***
(v)	***	***	***	***	***	***
(vi)	***	***	***	***	***	***
(vii)	***	***	***	***	***	***

4. उपर्युक्त प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद समिति ने मामूली संशोधनों के बाद इन प्रतिवेदनों को स्वीकृत किया। समिति ने अध्यक्ष को प्रतिवेदनों के प्रारूपों को अंतिम रूप देने और उन्हें सदन में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

***